ممبئی کا سب سے بڑا یوگدان ہے اور ممبئی ایک مہانگر ہی نہیں بلکہ منی ہندوستان ہے، جہاں ہندوستان کے ہر علاقے سے لےکر دنیا بھر کے لوگ بستے ہیں۔ اس لئے سرکار کو ممبئی کی لوکل ٹرینوں کے سدھار کے لئے جلد قدم اٹھانا چاہئے۔

"ختم شد"

STATUTORY RESOLUTION

Amendment of First Schedule to Customs Tarrif Act, 1975

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Sir, I move:

> "In pursuance of sub-section(2), of section 8A of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House approves of Notification No. 81/2007 - Customs, dated the 3rd July, 2007 [G.S.R. 462(e), dated the 3rd July, 2007] which seeks to amend the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 so as to enhance the rate of customs, duty applicable to goods falling under heading 2204 or 2205 or under tariff item 2206 00 00 from '100%' to '150%'."

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT BILL

The Apprentices (Amendment) Bill, 2006

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND ENPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Apprentices Act, 1961 be taken into consideration."

Mr. Deputy Chairman, Sir, as the hon. Members are aware that a large number of persons undergo apprenticeship training in various industrial establishments, under the Apprentices Act, 1961, in order to become more employed. The National Apprentice Scheme was started way back in 1959 on voluntary basis to prepare skilled manpower for industry by using training facilities available in the industry.

As the response from the industry was not enthusiastic, the Government felt it necessary to regulate the Apprenticeship Training Scheme by enacting the Apprentices Act, 1961 which came into force on 1.3.1962. Initially, the Act was envisaged for providing training to the school leavers as trade apprentices, but it was further amended in 1973 to include training of graduate and diploma engineers as graduate and technician apprentices.

---

† [Transliteration in Urdu Script].

With the passage of time, importance of apprenticeship training amongst the user industry grew manifold and the need was felt to enlarge the scope of the Apprenticeship Training Scheme for the benefit of industry by bringing training of 10+2 vocational scheme as Technician Vocational Apprentices by further amending the Act in 1986. It is my pleasure to inform you that my Ministry is making continuous efforts to make Apprenticeship Training more responsive to the needs of the industry, and, in this regard, the Act was further amended in 1997 to improve the performance of the Apprenticeship Training Scheme qualitatively and quantitatively.

The Apprenticeship Training is now being implemented in 159 trades in 23,800 industrial establishments in 254 groups of industries. Out of 2.58 lakh seats allocated for apprenticeship training, 1.85 lakh youth are undergoing apprenticeship training for gainful employment. I would also like to share with you that apprenticeship seats are also reserved for youth belonging to SC/ST categories. The duration of apprenticeship training period varies from six months to four years and stipend is paid to apprentices per month, which varies from Rs. 1090 to Rs. 1620 per month.

The Central Apprenticeship Council, a tripartite and apex statutory body, which advises the Central Government on all policy matters in apprenticeship training, in its 29th meeting held on 29.10.2002 under the Chairmanship of the Minister of Labour made the following recommendations: -

> to provide reservation for Other Backward Classes (OBCs) under the Apprentices Act, 1961 because the Central Government as well as various State Governments have made reservation for OBCs in the matter of employment and it became necessary to consider reservation for OBCs for admission in Industrial Training Institutes, and also for engagement of Apprentices under Apprenticeship Training Scheme to meet the requirement of skilled/semi-skilled workers belonging to OBC in employment.
>
> to amend the Apprentices Act, 1961 to provide for imparting of related instructions by the employers instead of appropriate Government because the cost of related instructions which is reimbursed at the rate of Rs. 30 per month per apprentice by the appropriate Government to the establishments is only 2 per cent of the monthly stipend paid by the establishments to trade apprentices. It also involves disproportionate amount of paper work, which encourages establishments to forego reimbursement of the cost of related instructions.
>
> to enhance flexibility up to 50 per cent in the matter of engagement of apprentices in a trade provided that overall quota fixed for the establishment remains the same as it will facilitate the industry to engage apprentices keeping in view more realistic employment potential, training facilities, and other relevant factors.

These are important amendments proposed through this Bill. I hope that the hon. Members will support the above recommendations proposed by me wholeheartedly

in order to make the Apprenticeship Training Scheme more relevant to the growing need of the industry. Further, it will also make the Scheme demand-driven and user friendly. With these words, I commend the Bill for consideration of the House.

The question was proposed.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उडीसा) **:** उपसभापति महोदय, यह एक छोटा सा बिल है, लेकिन इसका रंग बहुत गहरा है और उसके साथ-साथ इस बिल में राजनीति भी बहुत गहरी है । मान्यवर, मैंने पहले भी लेबर के एक प्रश्न के उत्तर के दौरान अतिरिक्त प्रश्न पूछते हुए कहा था कि कम से कम देश का यह सौभाग्य है कि सत्ता केन्द्र के एक अत्यंत नजदीक वाले, वास्तविक सत्ता केन्द्र के एक अत्यंत निकट वाले नेता अब हमारे लेबर को डील करने के लिए मंत्री के रूप में आ गए है ।

महोदय, आज जो सरकार चल रही है , इस सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले जो लोग है, इनका राजनीतिक आधार लेबर है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, श्रमिक आंदोलन, लेबर की बात बोलते-बोलते ये लोग संसद में पहुंचे और एक साइजेबल संख्या में पहुंचे । उसके बाद से ये लोग सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे है और यह सरकार चल रही है । अब यह सरकार चल रही है या सरकार घिसट रही है, इसका सारी दुनिया को पता चल गया है । हमारे यहां 10 तारीख को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ और संसद का सत्र भी चालू हुआ । हमने 13 तारीख को अपने 13वें उपराष्ट्रपति, अपने सदन के सभापति का स्वागत किया । उसके बाद कितने ही भारतीय, जहां तक कि दुनिया के बहुत सारे पत्रकारों से लेकर बहुत सारे इंटलेक्चुअल्स प्रतीक्षारत रहे कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की यह सरकार चलेगी या नही चलेगी ? कुछ दिन संसद का काम नही चला, बार – बार गतिरोध हुआ और उस गतिरोध के लिए हमें दोषी ठहराया गया कि विपक्ष गतिरोध पैदा करता है । ऐसा नही है, महोदय ।

श्री उपसभापति : आप एप्रेंटिस बिल पर बोलिए ।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, मैं एप्रेंटिस बिल पर आऊंगा । मैंने कहा कि यह बहुत छोटा बिल है ।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल (पंजाब) **:** आपको यह छोटा नजर आ रहा है?

श्री रुद्रनारायण पाणि : नही, हमने छोटा नही कहा ।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : आपने कहा ।

श्री रुद्रनारायण पाणि : नही, मैंने नही कहा । बिल का बहुत महत्व है, लेकिन उसका जो पैराग्राफ है, उसका जो वाक्य है, वह बहुत ही छोटा है । इसको समझने के लिए थोड़ा धीरज रखिए ।

महोदय, मैं कह रहा था कि न्यूक्लीयर डील पर हिंदुस्तान की संसद में ...(**व्यवधान**)...

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात) **:** यहां न्यूक्लीयर डील कहां से आ गया? ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : हिन्दुस्तान की संसद में न्यूक्लीर डील के बारे में बढ़िया सी बहस होगी...(**व्यवधान**)... वास्तव में इसमें क्या है, यह पता चलेगा लेकिन न्यूक्लीयर डील पर चर्चा ही नही की ।

श्री उपसभापति : अब आप इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी पर बोलिए ।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, इस बिल पर बोलने के लिए...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : क्या कुछ भी नही हैं ?

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, यह प्रास्तावित है । इस सरकार ने न्यूक्लीयर डील पर चर्चा क्यों नही कराई ?...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : पाणि जी, आप सब्जेक्ट पर आइए ।

श्री रुद्रनारायण पाणि : उस पर डिसकशन न कराते हुए आप एक के बाद एक बिल यहां लाते है । यह बिल तो पास हो जाएगा,किन्तु इस बिल के बारे में स्टेडिंग कमेटी ने क्या कहा, इसको आपको धीरज से सुनना चाहिए ।

स्टेंडिंग कमेटी ने कहा- इसके बाद समिति ने प्रशिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2006 के संबंध में 16वें प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया । आगे इसमें यह है – इस संबंध में समिति का मत यह था कि प्रशिक्षु अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों, विशेषतया निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रशिक्षण स्थान आरक्षित करने के मुद्दे पर तभी विचार किया जाए, जब उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित करने के मसले पर गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशों के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई निर्णय कर ले । अतः समिति ने इस विधेयक को सरकार को लौटाने और यह आग्रह करने का निर्णय लिया कि सरकार इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से परामर्श करे और तभी कोई नया विधान लाए, जब कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के इस मुद्दे पर कोई नीतिगत निर्णय ले लिया जाए । महोदय, अभी न्यूक्लिअर डील पर मैं बोला तो उनको बहुत परेशानी हुई, किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण के बारे में सरकार अभी क्या फैसला ले रही है? सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है । केवल राजनीति करने के लिए एप्रेंटिस में आरक्षण लाते है, लेकिन एप्रेंटिस की व्यवस्था कहां है? महोदय, हम OBC के लिए आरक्षण के कतई विरोधी नही है । 90 के दशक में जो आंदोलन हुआ था, हमें कमंडल वाले बताया गया था, लेकिन हम मंडल कमीशन के कतई विरोधी नही है । मंडल कमीशन के कुछ वर्गो को लेकर लोगों ने तो पोलिटिकल प्वाइंटस स्कोर किए थे । हमारे नेता, मैं एक-एक का नाम गिना सकता हूं, जो कि देश के नेता हैं और दुनिया में जिनको लोग जानते है, वे किस वर्ग के हैं? आप जात-पात पूछेंगे । माननीय आडवाणी जी की जात क्या है? आप जात-पात पूछेंगे । कल्याण सिंह जी से लेकर नरेन्द्र मोदी जी तक ले लीजिए, सब OBC वर्ग में आते है । भारतीय जनता पार्टी कतई OBC वर्ग की विरोधी नही है ।

न्यूक्लिअर डील पर चर्चा न करते हुए आप इस बिल को ले आए । कल रेलवे की सप्लिमेंट्री ग्रांटस पर जब चर्चा हो रही थी तो हमारे नेता माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने सही कहा था कि आपने वित्त मंत्रालय के लिए सप्लिमेंट्री ग्रांटस को जल्दी से पास करा लिया, आपने रेलवे मंत्रालय के लिए सप्लिमेंट्री ग्रांटस को जल्दी पास करा लिया, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा है, शायद आवश्यकता पड़ने पर इस संसद को आप प्रिपोन्ड कर देंगे, इस अधिवेशन के समय में आप कटौती कर देंगे और आगे चलकर आप अपनी मनमानी करते रहेंगे । ठीक है, आपके पास आज तथाकथित बहुमत है, लेकिन वास्तव में सरकार के पास बहुमत है । या नही, यह दुनिया जानती है । इस तथाकथित बहुमत को लेकर आपको जो करना हो, करिए । आप एप्रेंटिस में आरक्षण की बात करते है, लेकिन आज एप्रेंटिस के लिए मौका ही कहां है, आज नौकरी के लिए मौका ही कहां है? Where is the scope of employment ? आप सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर रहे है । हमारे वामपंथी मित्र पुरजोर से कहते है, SC, ST बिल पर

बोलते समय भी कहते हैं कि आप पब्लिक सैक्टर को प्राइवेटाइज़ कर रहे हो और प्राइवेट सैक्टर में SC, ST के लिए आरक्षण का मौका ही कहां है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा और जानना चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर में SC, ST को आरक्षण देने के लिए सरकार की वास्तव में नीति क्या है? मंत्री जी कृपया इसको स्पष्ट करें । अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा समझ रहे है कि केवल पोलिटिकल बात करके, अगला चुनाव आ जाएगा, हम राज करते रहेंगे, तो ऐसा नही होता है । …(**व्यवधान**)… पेपर गुम नही होता है, पेपर गुम होने का कोई चांस ही नही है । मंत्री महोदय ने अपना पूरा का पूरा भाषण पढ़ा, बढ़िया से बढ़िया ड्राफ्ट करके पढ़ दिया, हम ऐसा नही करते हैं, हम दिमाग लगाकर, बुध्दि लगाकर भाषण करते है । हम पेपर नही पढ़ते है ।

महोदय, यह जो बिल है, यह तो ऐसे ही पास हो जाएगा । एप्रेंटिस के लिए अभी जो पैसा दिया जाता है, 1,090 से 1,620, उसमें बढ़ोत्तरी की जाए और जितने कारखाने हैं, अभी भी जहां एप्रंटिद की गुजांइश है, वहां कैसे एप्रेंटिस की सभी सीटस भरी जाएं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसके साथ-साथ जिस कम्पनी या कारखाने में लोग एप्रेंटिस लेते है, उनको वहीं पर नौकरी देने के लिए कैसे व्यवस्था की जाए, इसके प्रति भी मंत्री महोदय ध्यान दें ।

मंत्री जी ने कहा था, बहुत प्रचार किया जा रहा हैं कि अगले सत्र में अनआरगेनाइज्ड सैक्टर के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव बिल आएगा । कब कम्प्रिहेंसिव बिल आएगा? जैसा महिला आरक्षण का बिल आप ला रहे है, उसी प्रकार का अनआरगेनाइज्ड सैक्टर के लिए बिल आप लाएंगे । 45 करोड़ की यहां लेबर फोर्स है, इनमें से अनआरगेनाइज्ड कितने हैं, यह मंत्री महोदय जानते है, सब लोग जानते हैं । इस अनआरगेनाइज्ड सैक्टर के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव बिल जल्द से जल्द लाया जाए । विभिन्न प्रकार के कारखाने जो प्राइवेट सैक्टर में होते हैं, उनमें भी आप apprentice लेंगे । उनमें जो शिक्षु होंगे, उनको कैसे फायदा हो, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द unorganised sector की लेबर के बारे में एक comprehensive Bill लेकर यहां आए । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at two o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri G. Sanjeeva Reddy.

SHRI G. SANJEEVA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity. I stand here to support the amendment proposed by the hon. Minister of Labour with regard to the addition of the other backward classes to the Apprentices Act. Sir, this addition is not going to be much useful to the working class and to the industry itself. Today, time has changed. The Minister must try to understand the situation existing in the industry as well as in the working class. The Apprentices Act was brought about in 60's. Today, after global economy was introduced in this country, the whole country was industrialised, the whole situation has undergone a big change. Suiting to these changes, the Act should also be amended accordingly. A new idea should be brought

about so that the Apprentices Act may be useful to the industry as well as to the workers. Today, it is not useful to anybody. Today, the Apprentices Act is not implemented by any of the industry in the country, what was implemented in 60's, 70's, 80's. Today, no industry is appointing apprentices, because apprentices are getting very meagre remuneration. They are getting about Rs.1600/- to Rs.2,000/-only. Even the private employers who employ apprentices are paying them about Rs.2,000-, Rs.3,000/-, Rs.4,000/-. Still, apprentices are not ready to go to the industry. The apprentice, specifically, say that engineers who have passed engineering, diploma-holders, vocational trainers, then, ITI, are already in shortage in our country. There is a shortage of skilled workers in the country. Therefore, it is going to affect the industrial growth of our country. It must be seriously taken into consideration by the Government, because this whole system, this whole thinking, whole practice is not going to be helpful to the present economic atmosphere which was introduced in this country. Industries are coming up in a big way, multinationals are also coming up. They are demanding for skilled workers. Sir, even for running our planes, we are bringing pilots from England. Pilots are coming from outside the country. Similarly, engineers are coming from outside the country. Highly-skilled welders are coming from outside the country. Whatever skilled workers are there in our country, they -because in our country, employers are paying less salary, less remuneration - are going outside the country. Skilled workers are migrating to other countries, like Middle East, America, England, Germany. All these countries are flooded with Indian technicians, Indian skilled workers, starving the Indian industry.

Today, the Indian industries are starving in a very big way. Sir, since I am in this field, therefore, I can tell this thing to my Government. 'Please look into it. Otherwise, it is going to affect the industrial growth of this country very badly. If you do not take a proper step, proper atmosphere would not be created. Therefore, the Labour Ministry has to understand this situation. Whatever the report says, the Apprentice Act has to undergo a big change in such a way that an Apprentice-cum-Training Act should be there.

Sir, with regard to remuneration also, today you are suggesting only Rs. 1600. For training purposes, who is going to be there for this meagre amount? Therefore, the minimum remuneration should not be kept less than Rs. 5000 so that it may be a little attractive for these people. It is not sufficient for the trainee who has passed the ITI or who is a diploma holder or for those engineers who are going for it in order to get a higher remuneration later. It is not sufficient for anybody to work there for two years, three years. Today, the apprentices are ineffective because the employers do not bother about the Apprenticeship certificate. They employ raw hand people, train them and utilise them for productive purposes. They require them for new technologies. Sir, to the workers whom we train, we give a certificate saying that on-job training was given to such and such person after passing the ITI. But the employer says, 'I myself can give a job training; what is the use of going for apprenticeship training?' Therefore, some sort of a change is required in order to attract the more skilled workers.

Another important point that I would like to mention, Sir, is that all matriculation people or tenth pass workers or young boys should be allowed to have training in the industry and a job guarantee should be given to them. Today, an apprentice can seek employment in an industry after working in a place as apprentice for two years.

Then they say 'since your training is over, you can go away from my industry and seek employment somewhere else.' Sir, finding employment somewhere is not easy in our country. Jobs are not available in our country for those workers who are unskilled or semi-skilled. The job availability is there for skilled workers or highly skilled workers. Therefore, they have to create an atmosphere where a tenth pass young boy can work in an industry and get some technical training, instead of asking them to go in for ITI or for some engineering course or for some diploma or vocational training. It is not working that well nowadays as it used to do previously. During 1960s or 1970s, it had worked very well and we used to have a quota in industry and in a ratio of 1:6 or 1:7 an apprentice used to be appointed. But today it has not been the practice. No industry is appointing the apprentice; no industry wants to recruit them. No industry wants to take these apprentices in their industries because they are always finding a shortage.

Sir, the small-scale industry is one of the important industries, but here the apprentices do not go at all. Sir, small-scale industries have got fifty per cent employment potential and they are producing almost fifty per cent of the country's production. At this moment, the point is how to help the small-scale industry, the medium-scale industry through these technicians. That has to be planned here. We are only planning for major industries, big industries. We are not taking any interest at all in the small-scale industries. The small-scale industries should be taken up properly so that a technician can be employed there. A trained technician is required for the industrial growth.

Sir, another point that I would like to mention here is that for the ITI and diploma holders, on-job training should be encouraged and self- employment scheme should be implemented. A person can be trained for self-employment. Today, we are training the workers so that they can seek job. Why not we go for self-employment? The Government of India should apply its mind. In China today, the self-employment scheme has been introduced in a big way and millions of people are employed through self-employment schemes. In this way, they are able to fight out the unemployment problem of the country. Similar to that, in our country also, there is a good scope for self-employment, provided we give a good technical training and a good financial assistance. Some work should be reserved for those younger people who adopt for this self-employment scheme. That may give a very big relief to our country and also to our industry. Sir, today, the employers themselves seek more workers; you may ask them. They recruit new hands and train them. Why does the Government want to spend money? Why are you not seeking the opinion of the employer? Industries must be asked to recruit 20 to 25 per cent of the people, raw hands, and train them at their own expenditure, because they earn good profit and they could provide them the training needed for that particular industry. We impart such training to people that is not required by the industry. Today, we need to impart training keeping in view the advent of new technology and new mechanised industries and that training could be imparted by the industries themselves. Such a clause should be included in the Apprentice Act. In fact, the Apprentice Act itself should be amended to be known as the 'Apprentice-cum-Training Act'. Such changes need to be introduced in the interest of the country. That is important; otherwise, shortage of trained and skilled people would have a bad effect on the country's industrial growth and employment potential. The country may not be able to attract investments if there is lack of skilled labour.

Therefore, I would humbly request the Minister for Labour to amend the Act keeping in view the prevailing situation and requirement. He may talk about Other Backward Classes, but there are no jobs and there are no training centres. Reservation for any caste or community would do nothing to help or benefit the poor people. They must create an atmosphere where workers could seek more jobs, get trained and earn more money. Migration of people to other countries seeking jobs could be stopped if our employers pay good salaries and sufficient money to the employees depending on their skills. Their skills should be recognized and valued by the Indian employers and they should be paid accordingly. Only then we could retain talent in this country.

With these words, I thank you, Sir, for giving me time.

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, शिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए आज जो शिक्षु (संसोधन) विधेयक, 2006 इस सदन में लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सरकार की मंशा सही है कि अन्य पिछड़े वर्गो को रोजगार मिल सके या अन्य पिछड़े वर्ग किसी भी रोजगार के लिए कुशल हो सकें । इस विधेयक के माध्यम से जो यह संशोधन लाया गया है, इसमें अन्य पिछड़े वर्गो को शामिल किया गया है । मुझे ऐसा आभास होता है कि सरकार की सोच सही है और उसने सही कदम उठाया है । लेकिन दूसरी तरफ एक शंका भी उठती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार आज जो यह संशोधन विधेयक लेकर आई है, यह इस सदन से पारित हो जाएगा, लोक सभा से भी पारित हो गया है, लेकिन यह कानून का रूप लेगा या नही लेगा, मुझे इसमें संशय लगता है । यह ठीक है । यह ठीक है कि सरकार ने कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया है । यह सरकार की सोच है या हम लोगों की सोच है कि इस देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और रोजगार के क्षेत्र में कुशल और निपुण लोग जाएं, लेकिन सरकार अन्य पिछड़े वर्गो को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और गैर-तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 27 परसेंटा आरक्षण देने के लिए विधेयक लाई भी ।

सरकार की सोच सही थी या गलत थी, मैं इस चर्चा में नही जाना चाहता । सत्ताइस परसेंट हॉयर एजुकेशन में, टेक्नीकल एजुकेशन में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का जो काम यहां किया गया है, वह आज भी सर्वोच्च न्यालय में लंबित है । मुझे कहीं न कहीं जरूर एक शंका लगती है कि इस संशोधन विधेयक का भी वही हाल न हो जाए, जो अन्य का हुआ ।

माननीय उपसभापति जी, सरकार जो यह संशोधन विधेयक लेकर आई है, मैं इसके लिए माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन यह काम और पहले होना चाहिए था । सरकार ने इसमें देरी की । महोदय, 7 सितम्बर, 2000 को श्रम संबंधी स्थायी समिति ने इस पर कहा कि अक्तूबर, 2002 में श्रम संबंधी जो स्थायी समिति थी, उसने कहा है कि केंद्रीय शिक्षुता परिषद द्वारा लिए जाने के बावजूद भी सरकार ने प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गो हेतु आरक्षण व्यवस्था के लिए नया विधान लाने में इतनी देरी क्यों की । श्रम मंत्रालय ने कहा कि हम जो विधेयक लाना चाहते थे, वह इस मंत्रालय से होकर, मानव संसाधन मंत्रालय से श्रम मंत्रालय में गुजरा और कैबिनेट में इसको ले जाया गया। उसी के तहत इसमें देरी हुई और इस संशोधन विधेयक को लाने में इतना विलंब हुआ । सरकार ने देरी से ही सही, इस विधेयक को लाने का काम किया है, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है:

उपसभापति जी, इस देश को आजाद हुए साठ वर्ष हो गए है । हमारे जैसे लोगों और हमारी समाजवादी पार्टी की मान्यता है कि समाज के जो कमजोर, शोषित और पिछड़े लोग हैं, जब तक उन्हें सशक्त करने का काम नही किया जाएगा, तब तक इस देश से अमीरी और गरीबी का फर्क दूर नही होगा । पिछले साठ वर्षो में आजादी के बाद से सरकारें चाहे जितना काम करती रही हों, उस दूरी को हम कम नही कर सके और वह खाई बढ़ती गई । जब तक इस दूरी या खाई को पाटने का काम नही करेंगे तब तक हम एक अच्छे समाज और सशक्त भारत का निर्माण नही कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए । इस संबंध में चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर रहे हों, डा. राम मनोहर लोहिया रहे हों, सभी की यह विचारधारा थी कि समाज के पिछड़े वर्ग को, शोषित वर्ग को, कमजोर वर्ग को आरक्षण देकर समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया जाए । इस संबंध में संविधान के अंदर भी हमने आरक्षण की व्यवस्था की है । इसके लिए अनुच्छेद 14, 15, 16 और 335 बनाने का काम किया है ताकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है वह इसका लाभ ले सके और देश की मुख्यधारा में शामिल हो सके ।

माननीय उपसभापति जी, यह जो शिक्षु संशोधन विधेयक लाया गया है, इसमें तीन प्रमुख बातें हैं । इस अधिनियम की धारा 3 (क) में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशिक्षण स्थानों के आरक्षण का उपबंध था । आज सरकार संशोधन ले आई है । इस संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्रेंटिस की सीटों को निर्धारित करने का जो अनुपात था, (**समय की घंटी**) उसको लचीला बनाने का काम इस संशोधन के द्वारा होगा ।

तीसरी बात यह है कि इस संशोधन विधेयक में सम्बन्धित शिक्षण समुचित सरकार के बजाय नियोजक के खर्च पर दिया जाएगा । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऐसा होगा, जो केन्द्रीय शिक्षुता परिषद के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवसाय के लिए समुचित होगा और ऐसे प्रशिक्षण से हम इस देश में कुशल जनशक्ति तैयार करने का काम करेंगे एवं जो प्रशिक्षु होगा, उसके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे । प्रायः यह देखा जाता था कि जब नौकरियों के लिए एड निकलते थे, तो उसमें कुशल व्यक्तियों की कमी हो जाती थी । निश्चित रूप से हमें इसमें सहायता मिलेगी और हम ऐसे लोगों को कुशल बनाने का काम करेंगे । लेकिन दूसरी बात यह है कि हमसे पहले जो माननीय सदस्य यहाँ बोल रहे थे , मैं उनकी बातों से अपने आपको पूर्णतः सम्बंद्व करते हुए कहना चाहता हूँ कि एप्रेंटिस में जो लोग जाते हैं, उनको वेतन के नाम पर, मानदेय के नाम पर इतना कम पैसा मिलता है कि जीवनयापन करना मुश्किल हो जाता है । मैं सदन के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ऐसे प्रशिक्षण लेने वाले हैं, हम जिनको तैयार करने का काम कर रहे है, उनको कम-से-कम इतनी धनराशि अवश्य दी जाए, आदरणीय राजनीति प्रसाद जी पाँच हजार कह रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि इतनी धनराशि जरूर दी जाए कि उनका जीवनयापन ठीक ढ़ंग से चल सके ।

मैं पुनः सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन में, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल करने की बात कही गई है, उसका समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूँ । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI K. CHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, this is an important Bill. Initially, I want to totally support the suggestions and the opinion given by my senior colleague, Shri G. Sanjeeva Reddy. He is the President of INTUC also. He spoke on

the Bill from his experience in this field. Regarding the Bill and its amendment provisions, there are three amendments in this Bill. Basically, the intention is to ensure reservation for OBCs in apprenticeship. Actually, it is a delayed one. But, there is no hesitation from our side to support it and such a provision was very much necessary. But, while looking at the overall economic scenario of the country with a global view, the need of the hour is that basic change in the Apprentices Act has to be *in toto.* With a holistic approach, we have to re-work the entire structure of this Act. That is my opinion. Why am I saying this? See, we are with an ambition to sustain the growth rate for which we have now initiated certain measures in the agricultural sector though distress has still not abated. To cater to the needs of the economy, training of the employment force is very, very significant. Now. India is in a special position. As far as Indian population is concerned, demographically, fifty four per cent of our population is below twenty five years. This is a rare placement amongst other countries of the world. So, the total available set up or the Infrastructure in the training field is not adequate to cater to the needs of the economy. Of course, in the two Budgets, we initiated certain expansion measures for the ITIs and polytechnics. It is there. I accept it. The ongoing job training in the industrial establishments is a vital area, which is being taken care of by The Apprentices Act, 1961.

After fifty years or so, we are not touching the basic lacunae of this Act. Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I want to lay stress on this point. One aspect is that Section 8, sub-section 3 is actually envisaging a kind of flexibility. In a sense, this flexibility is among trades. But there is no point to enhance the available quota. Quota is the same and the flexibility is working within that. The actual demand is to enhance the' quota itself. That is the need. It is not addressed here. That is why I said that it is not a holistic or comprehensive approach.

Another area is relate to instruction charges. There is no harm in taking it away from the Government and entrusting it on the employer. It is coming to only thirty or thirty+ rupees per head in the course period.

But along with this thing, I would like to specifically ask the Minister to look into the factor where the stipend rates are now provided. INTUC President, and, my colleague, Shri Sanjeeva Reddy rightly pointed it out. So, a proper measure should be undertaken by the Government to enhance that amount so that, at least, the basic needs can be fulfilled. They are coming to industrial establishment from distant places and stay there. They get canteen facilities and stipend and that is all. I myself worked as an apprentice for a period of two years in an industrial establishment. I know it. For accommodation or other such things, there is no provision. So, that area should be addressed properly to see that these things are extended to them.

Sir, the question of stipend is not the only point. I would like to mention here that a kind of exploitation is also going on in the apprenticeship. It is applicable both to the public and private sector. Against the permanent vacancies, engagement of apprentices is taking place in the country and they are heavily under paid. There is no mechanism to monitor or to discourage this menace. Is there such a provision in this Act to curb that? It is not there. Nowadays, the contractual employment, outsourcing is the practice in the industrial sector also as it is there in other sectors. The victim is the worker or the apprentice, the unemployed youth.

So, proper monitoring mechanism should be evolved to see that it does not happen in our industrial establishments. While I am saying that this is applicable to public sector industries also, it means that the public sector is acting as a model employer in the country, and, in such a system also, this is happening by which the number of permanent workers is coming down in various industrial establishments, saying it is the situation in every industry. But it is there. I can cite immense examples. So, that is the major area where we have to revisit to see that it is effectively curbed.

Another matter to which I would like to put before the hon. Minister is that, in the coming years, Asia is going to become a major hub for the skilled and talented workforce. And, India too is going to be one major contributor to this. With that perspective in mind, with a futuristic perspective, we have to re-structure the entire thing with a visionary approach. I totally agree with the limited purpose of this amendment. I have said it earlier. There is no dispute on this. But, we are not addressing the real issue. It is a piecemeal type of an amendment. It is very necessary from the social point of view. I accept that. But, while touching an area where the enactment took place 50 years, these major issues and the changes occurred in the economy and in the country in toto have also to be taken care of. I am expecting a proper legislation at the very first chance. With these words, I am concluding. Thank you.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. On behalf of AIDMK Party, I welcome the Apprentices (Amendment) Bill, 2006. I come from Tamil Nadu a State that had championed the cause of social justice for the last 75 years. Great leaders like Periyar, Anna and MGR have spent their life for the empowerment of the deprived. My leader, Puratchi Thalaivi, gave Constitutional guarantee for the 69 per cent reservation in Tamil Nadu by getting included in the Ninth Schedule of the Constitution. Hence, our support for this Bill is wholehearted. Sir, clause 2 of the Apprentices (Amendment) Bill, 2006, seeks insertion of a new section 3B in the principle Act of 1961. It is for reservation of training places for Other Backward Classes in designated trades. It is a welcome move. There is no other thinking about it. However, I would like to point out that a recommendation in this regard was made by the Central Apprentices Council way back in 2002. After an inordinate delay, now the Government has come up with a Bill for reservation of training places for OBCs. Now, it should be implemented at the earliest. Sir, the second amendment aims to provide flexibility up to 50 per cent in the matter of engagement of apprentices in the trade. As per the principal Act, the flexibility of 20 per cent is presently available. I have apprehension that the proposed amendment may benefit only the traders, not others. The apprentices are paid only stipends, not salary. As such, this may indirectly benefit employers. Moreover, this may be a hindrance to the youths in getting permanent jobs. So, suitable amendments should be carried out to the principal Act. In effect, the proposed amendment will reduce the number of permanent jobs available in our industrial establishments. Moreover, stipend to apprentices should also be increased, when 50 per cent of the employees will be apprentices and 50 per cent of the work will be done by them. With above suggestions, I welcome this Bill. Thank you.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) **:** उपसभापति जी, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया, इस के लिए आप को धन्यवाद । मैं जिस जगह से आता हूँ, वह बिहार राज्य है, जहां से माननीय

कर्पूरी ठाकुर जी आते थे और माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी आते है। इन लोगों ने और हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने पिछड़ों के लिए जो सिध्दांत बनाया, वह सिध्दांत यू.पी.ए. की सरकार ने लागू करना चाहा, लेकिन कहीं न कहीं उसमे अव्यवस्था हो जाती है। सरकार कानून बनाती है, लेकिन कहीं न कहीं अव्यवस्था हो जाती है और वहां मामला रुक जाता है।

महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और यह स्वागत इसलिए करता हूँ कि यहां हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने ग्रामीण रोजगार के लिए 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की हैं कि अगर गांव में कोई बेरोजगार हे, तो उसको साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा या रोजगारी भत्त मिलेगा, उसी तरह इस बिल से जो अनएंपलायड लोग है, जिनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नही है,जो कारखानों में काम करना चाहते हैं, मगर ट्रेनिंग नही मिल रही है, ऎसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देकर उनको skilled बनाया जाएगा, जिससे फिर उनको किसी अच्छे कारखाने में काम मिलेगा।

महोदय, मैं यहां सदन में एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह कहना चाहता हूँ कि आज आप किसी शहर में चले जाइए, आपको अनएंपलायड लोगों में जो ग्रेजुएट लोग है, जो एम.ए. पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बी.ए. पढ़े-लिखे लोग हैं, वे सब मिलेंगे, लेकिन skilled यानि ट्रेनिंग पाये लोग, जो कारखाने में अच्छा काम कर सकते हैं या जो बढ़ई, मिस्त्री का काम करते हैं, जो बढ़िया आर्किटेक्ट का काम कर सकते हैं, ऎसे लोग आपको नही मिलेंगे या मिलते हैं तो बहुत कम मिलते है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां ट्रेनिंग की व्यवस्था नही है और अगर कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था है, तो वैसे लोगों के लिए हैं, जो haves हैं, जो पहले से संपन्न है और जो have-nots हैं, जिनमें ज्यादातर पिछड़े लोग है, वैसे लोगों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था नही है।

महोदय, माननीय मंत्री जी जो यह बिल लाए है, यह बहुत ही सराहनीय बिल है और यह इसलिए भी है कि वैसे लोगों के लिए, अदर बैकवर्ड लोगों के लिए इससे ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसा मेरे एक मित्र ने भी यहां कहा कि आप उनको केवल कैंटीन की फैसिलिटी मत दीजिए, यानी जो ट्रेनिंग करने वाले लोग है अदर बैकवर्ड क्लास के लोग है जो have-nots लोग है, उनके लिए स्टाइपंड वगैरह की भी व्यवस्था कीजिए। हमने देखा है और अपने एक मित्र से भी मैंने पूछा कि इसमें कोई स्टाइपंड वगैरह का कुछ है, तो उन्होंने कहा कि इसमें स्टाइपंड वगैरह का मामला नही है। उन कारखानों में, जहां लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, जो वहं ट्रेनिंग करने जाएंगे, अगर आप उनके लिए केवल कैंटीन की व्यवस्था करेंगे, तो वे लोग ट्रेनिंग नही कर पाएंगे। वे गरीब लोग हैं, कैसे ट्रेनिंग कर पाएंगे? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि जो आदमी किसी कारखाने में ट्रेनिंग लेने जाए, उसके लिए कुछ पैसा, कोई स्टाइपंड आपको निर्धारित करना चाहिए और कानून में भी इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि कितना पैसा उनको कारखाने वाले देंगे। अगर वे पैसा नही देंगे तो मैं यह कह सकता हूँ कि ये लोग ट्रेनिंग ले ही नही पाएंगे, क्योंकि अगर उनको किसी बड़े शहर में एप्रेंटिसशिप के लिए मौका मिला है, तो वहं उनके रहने का खर्चा ही इतना होगा कि वे वहां अपनी ट्रेनिंग नही कर पाएंगे। इसलिए इस बिल का समर्थन करते हुए मैं फिर से यह अनुरोध करुंगा कि उनके लिए पैसे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े ट्रेनिंग स्कूल होते है, आई0टी0आई0 के जो बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेज होते है, वहां पर होस्टल की व्यवस्था होती है, मेरा कहना यह है कि जो ट्रेनिंग करने वाले लोग है, वहां उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे जहां जाकर ट्रेनिंग लें और उनको जीवनयापन के साधन मिल सकें।

मैं फिर से आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरी इन बातों को जरूर ख्याल रखें। मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me the floor to talk on this Bill. Sir, the Bill is crawling at a very slow pace. Originally, it was supposed to be presented here by Shri Chandrasekhar Rao. Now, it is being piloted by Shri Oscar Fernandes and I don't know by the time it actually becomes an Act and operative, how many changes will have taken place. There are three elements in the Bill and I was expecting some clarifications from the Minister's initial statement. It did not come. He read out the statement that is already enclosed with the Bill, which is not quite sufficient and I would very humbly submit that in replying to the debate, the Minister would give clarifications on a certain number of subjects. Sir, the purpose is to increase the flexibility in the number and increase the number of Apprentices. There are two questions that occur to a person like me. Firstly, having a larger number of apprentices is a matter of advantage for the employer also. It's a matter of advantage for the society, for those who expect to become enrolled in the industry. But, the employers also get cheap labour or cheap operatives to work in their hands. As was mentioned by Rajniti Prasadji, unless we stipulate as to what would be the stipends remuneration, it would be futile to talk about the percentage of trainees that ought to be included.

Sir, the proportion of twenty per cent for management of graduates itself appears to me too high. For example even in the Administrative Services in India, the proportion doesn't go beyond ten per cent including two years' of probation. Why are you imposing a percentage of twenty which was high enough as it is? And if you make it 50 per cent, you will bring down the quality of training because for every apprentice that you engage, there has to be some kind of backup or some kind of support - people who will look after their training, who will see to it that they get properly trained and, at the same time, they are also given the necessary theoretical training. Unless that kind of a provision is made, talking about 20 or 50 per cent would not make any sense. I would request the hon. Minister to reveal to the House exactly the mathematical basis on which he came to the conclusion of increasing from twenty per cent in 1961 or 1971 to 50 per cent in the year 2006.

Secondly, Sir, the idea that there should be a theoretical training that should support the practical training itself is a very good thing. In fact, the two go together. Because we use the word 'apprenticeship', the idea is not very clear. In modern industry, the word that is used is 'Training within Industry', TWI. And if you had used the word 'TWI', I think, it would have been quite clear that the training to be given is not only of a practical industry, but also of a theoretical industry. What I have not understood is, why is it that the Government which carried the financial responsibility of this theoretical training till the year 2006, is suddenly trying to shirk the responsibility and hand it to the employer? At the same time, it is imposing an

additional burden of what is called the social justice, the social equity. When that kind of burden is imposed on the employer, there should be an attempt to make the engagement of apprentices more attractive to the employers. Instead of that, you are making it less attractive. I would like to have some explanation on that subject also.

The third thing is about reservation for the OBCs. I do not understand why this third purpose was added into the Bill. There could be two motives. Number one; of course, there is some kind of a political competition to get laurels about giving the OBCs their share, and some Ministers are trying to monopolise the whole credit. Possibly, our Minister of Labour is in the race. But, I think, there is another risk. The two aspects, increasing the flexibility and increasing the theoretical training aspect, would have come in as a welcome measure, but because you have added the OBC reservation aspect, it is more than likely that along with other OBC Bills which are pending in the Supreme Court, this Bill will also be stayed and even the good parts of this Bill would not become operative.

Sir, on three occasions, in this House, I have opposed the Bill on the question of OBC reservation, and every time, I have given the arguments and every time, I have asked for division and voted against it. ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, will you please behave like a whip? And every time, I have said that this Bill will not go through the Supreme Court and it has not gone through the Supreme Court.

While the present and the last amendment still stands stayed I do not really understand why the Ministry of Labour and Industry is in such a hurry to get the OBC quota for apprentices.

Sir, there are a number of arguments which I briefly summarise. The merits and advantages brought in by the system of reservation have not been proven at all. There are some advantages and some disadvantages, but the greater disadvantages have been in the nature of politicising the society and making the society more caste conscious.

Number two, by the year 2010, in any case the entire policy of reservation is due to be reviewed, and at this time, this unseemly hurry of showing that certain people care more for the OBCs than the others, appears to be entirely politically motivated.

Sir, the question of creamy layer has not been settled yet, and even the Supreme Court has asked what is the statistics that you have about the total number of people belonging to OBCs and how is it related to the number of posts that are reserved. Sir, in this Bill you will find that the actual wording is that the proportion is not described. If they had said 27 per cent, that would have actually made the things easier. But what they say is: "Such as may be prescribed, having regard to the population of Backward Classes in the State concerned." So, the proportion is, again I do not know why, left to the employer or to the apprentice adviser. It is not very clear.

And, Sir, the most important thing is, I tried to go through the annexed original Act, 1971, and whatever is annexed here does not contain the provision which makes a reservation, in the apprenticeship clause, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Now, I do not understand what forms the basis of having the addition of section 3B when section 3A itself is not complete. I would like the Minister to kindly give an explanation on that subject also.

Sir, as I voted against all the Bills providing reservation for the OBCs up to now, I am going to keep my record. Unless the Minister is able to explain why he has found it necessary to add this OBC factor in an otherwise healthy Bill, I am going to oppose the Bill, Sir, and if it comes to a vote, I am going to ask for division; kindly note that, and I am going to vote against it. Thank you very much, Sir.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभापति महोदय, मैं इस शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2006 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि भले ही देरी से ही सही, लेकिन वे इस विधेयक को लेकर यहां आए हैं, ताकि अन्य पिछड़े वर्गो का हित हो सके।

उपसभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से बाबा साहब डा अम्बेडकर को उध्दत करना चाहूंगा। जब बाबा साहब डा. अम्बेडकर , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची बना रहे थे उस समय तथाकथित कुछ नेतागण "ऊंचा बनो" अभियान चला रहे थे और जिसके कारण अनुसूचित जाति में बहुत कम लोग आ पाए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को बाबा साहब ने आरक्षण तो दिया लेकिन जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उसके प्रति भी बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर जागरूक थे। उनके प्रति भी सजग थे, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 340 में उन्होंने व्यवस्था दिया कि पिछड़े वर्गो के हितों का अध्ययन करके आयोग बनाया जाए। आयोग अध्ययन करके रिपोर्ट दें और उसके अनुसार उनको भी आरक्षण दिया जाए । हमारा मानना है कि पहला आयोग काका कालेलकर का आयोग तथा दूसरा आयोग मंडल आयोग, उसी संविधान के अनुच्छेद 340 की उत्पत्ति है। काका कालेकर आयोग तो कतिपय कारणों से लागू नही हो सका,लेकिन मंडल आयोग जरूर लागू हुआ। हमारा मानना है कि जब मंडल आयोग लागू हुआ,उसी समय इस प्रशिक्षु विधेयक में भी संशोधान करके उसी समय लागू कर देना चाहिए था। लेकिन मंडल आयोग ने जो व्यवस्था दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्गो की आबादी 52 परसेंट हैं। 52 परसेंट के लोगों को 27 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था दिया था, लेकिन 1961 में जो यह एक्ट बना था उसके धारा 3(ग) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गो को नही थी और जब मंडल आयोग लागू हुआ, उसके बाद ही इसमें संशोधन करके लागू कर देना चाहिए था, लेकिन चाहे सरकार की जो भी परिस्थिति रही हो, लागू नही हुआ। विलंब हुआ। आज मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम देर आए, दुरुस्त आए। पिछड़ा वर्गो के हितों को लेकर के आए और यह एक आवश्यक कदम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ही साथ इस विधेयक के धारा 3(ख) में अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह सही है और इसको लागू करना चाहिए। हर राज्य को जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण की व्यवस्था है, यह भी निवेदन करेंगे कि हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रही हैं, मैं तो इस सदन के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और पिछड़ा वर्गो को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह ही व्यवस्था होनी चाहिए ।

साथ ही साथ हमारे बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को मानदेय कम मिलता है, यह वास्तविकता है। मंहगाई को ध्यान में रखकर मानदेय और उनके रहने , आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इन्ही सबकी प्रत्याशा में इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद।

SHRIMATI N. P. DURGA (Andhra Pradesh): I welcome the Bill moved for consideration by the hon. Minister as it is in tune with the aspirations of the Other

Backward Classes in the country. Sir, the objective of the parent Act is to regulate and provide training to apprentices in industry and utilise the facilities available in the industry for imparting on-the-job practical training, which varies from 6 months to 4 years, to technical students. It was amended thrice since its enactment in 1961-firstly, in 1973, to bring in engineering and technology as graduate or technician apprentices; secondly, to include 10+2 students who come from vocational stream of education; and thirdly in 1996. Now, I think, there are only 153 trades designated for trade practices and there are only 2.3 lakh seats available in establishments of Central and State PSUs and private sector. Now, in this era of globalization, productivity and production have to increase and this is possible only through skill upgradation of the workers. And, now, many more trades have come in particularly in IT, telecommunications, etc. So, I request the hon. Minister to designate more trades for trade practices. The other point is that now we have got only 2.3 lakh seats available in all establishments. With disinvestment, mergers, lockouts, etc., these seats have also come down in the CPSUs and State PSUs. So, I request the hon. Minister to make sure that private establishments or industries provide training to more and more apprentices by increasing their mandated strength of in-take. The problem is that private companies are not inclined to engage apprentices as per the quotas fixed for them in relation to the skilled workers employed by them. To address such issues, there are State Apprenticeship Advisers to make sure that private companies or industries strictly adhere to norms. But the problem is that the State Apprenticeship Advisers are hesitating to take legal action against the defaulting companies. Even the Government is not keen to address this basic problem. To address this problem effectively, the Standing Committee on Labour has recommended increasing the penalty under Section 31 which is now Rs. 500 to a minimum of Rs. 3,000 and maximum of Rs. 6,000, in 1995. But, when the Act was amended in 1996, this recommendation was not accepted. So, now, the penalty is only Rs. 500 if any private company fails to comply with the provisions of the Act. So, I strongly believe that this has to be enhanced to, at least, a minimum of Rs. 25,000. I don't agree with the argument of the DG of Employment and Training who says that we need to play a positive and proactive role in persuading the employers of private and public sector rather than going in for punitive approach. But, when you are not able to persuade them, the option left before you is nothing but penalizing, them. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to increase the penalty.

I wish to know from the hon. Minister is whether there is any scheme before the Ministry for apprenticeship under which unskilled jobless matriculate youths are trained in different industries, because we also have more and more non-technical and unskilled jobless youths in the country screaming for jobs. If there is any such scheme, I request the hon. Minister to explain the same.

Even though it is welcome that the Government is now making it mandatory for employer to meet the expenses required for training in a company; I wish to know the reasons behind this shift from meeting the cost by Government and now imposing on the employer by replacing Section 10(2) of the Act.

Finally, it is good that Bill paves the way for reservation for OBCs in apprenticeship training. But, I did not find any mechanism which ensures strict implementation of the objective of the Bill. So, I request the hon. Minister to explain how he is going to ensure strict implementation of the proposed legislation. Thank you.

3.00 P.M.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I fully support the Apprentices (Amendment) Bill, 2006. This Bill is very much essential. The downtrodden people chose to go in for school level education, but due to poverty and social conditions, they could not pursue it further. Then they went in for industrial training institute, which was contemplated in the Third and Fourth Five Year Plans. This enactment was made during the period of Pt. Jawaharlal Nehru. His ambition was to bring the people to develop their skills and develop themselves, through their skill, for a better life. They have completed technical education by theoretical methods; but, practically, they are yet to learn. They have to come within an establishment and learn how production or any such thing is happening within the discipline of establishment. This is the first entry which the Government of India has provided for them, by way of apprenticeship, allowing them to go and enter into an establishment or an industry and learn the skill. If a person has a better skill and he is able to exhibit his skills, then, naturally, the establishment itself would absorb him as one of the technically qualified persons because he has got a formal certificate, and he has proved his eligibility. Therefore, this system has to continue; it has helped a lot of people; in fact, lakhs of people have been benefited. Now, the hon. Minister, who is a dynamic person, has done a lot of things during his short period as Labour Minister, in setting the house in order in his Ministry, which is a very, very important Ministry. It has to be recognised even above the Ministry of Finance. But our system is not exposing to that level the Ministry of Labour. The Ministry of Labour is the real Ministry which addresses issues of 90 per cent of the people who are living here in India. As Shri Arjun Kumar Sengupta has said, about 77 crores of our people are *Aam admi,* that is, those living below the poverty line, not having even Rs.5-10 for their daily food. Out of these people, 80 per cent belong to the SCs, STs and OBCs. Therefore, these people ought to be guided. Even though we are spending a lot of money, and we are propagating what our Government's policies are, etc., these people are not having the facility to understand in which way they have to go, where they can reach and what their future is. They cannot decide it. Their families are like that. My friend from Maharashtra might feel happy asking for a division whenever the OBC issue comes up. But he has to understand how many crores of people are living in Maharashtra, especially in Mumbai, in poverty conditions, and they all belong to the SC, ST and OBC categories. He is playing his role of a Member here. He has got every right to do so. But we are playing with the lives of crores of people. These people are treated like animals in the industry. They don't have any job at all. A person, who snatched a gold chain, may belong to a minority community or, maybe, he comes from a suppressed family background. But how he was treated! This is the society we are living in. We are not living in the United States or Europe to give every person an opportunity for a living. The opportunity is taken away by themselves, and that is why, terrorism has come in. What we see is that there is strike for everything, and people are being killed here and there. According to the Constitution-makers, reservation had to be completed within a period of 20 years. But we have not accomplished it yet, and we have not satisfied the conditions. We have not given them an opportunity, given them a place in the society, as envisaged in the Constitution, We then extended it for 20 years more, but could not complete it. Even after 60 years, we have not completed it. Even

now we have not filled up the vacancies in Government Departments in respect of SCs, STs and OBCs. We have not fulfilled our obligation. How can you say that we are asking for reservation for everything, without fulfilling the obligation enshrined in the Constitution? You have to continue it even if it is meant for centuries. It only shows your inefficiency. The system is not responding properly. Therefore, I appreciate the hon. Minister for taking this belated attempt, at least, now by bringing in this Bill in favour of people who are poverty-stricken. We are not extending this benefit for the IIT people; we are giving this benefit to those in the Industrial Training Institutes. Persons, who are in IITs, get jobs on the campus itself, and they get salary as high as Rs. 2 crores. We are spending tax-payers' money on them. But we are not allowing them not to pay back that money which is due for the poor people. But, here, a person, who has passed his Tenth Standard, joins the Industrial Training Institute and gets a certificate after ten months, and he is just being assured of a stipend of Rs. 1,500. But he wants to develop his skills further so that he gets a proper job. But we have not been able to give him a job. And he goes to a foreign country not because of his lure of foreign employment, but because he does not get a job here.

We have been raising thi issue everyday. Just recently, nine people from my constituency had come to meet me; they had been deported from Singapore because they couldn't get visas. They had gone there for jobs. You cannot give them jobs here in India. My friend, Shri G. Sanjeeva Reddy, was saying that there was scarcity. Why is there scarcity? It is there because we have not been giving proper jobs to them. I know, in my constituency, from where they have also voted for the hon. Finance Minister, Shri Chidambaram, 18 year old girls get just five rupees for an eight-hour duty. Where are the law enforcement authorities there? Now, Rs. 1,500 has to be paid to an apprentice. For what? It is for development of his skills. If he has the skill then the system can absorb him. But, are they absorbing him? Now, we have this unit of BHEL, a public sector undertaking, at Trichy. A lot of people appear in this examination for entering into apprenticeship. Thousands of people have been waiting. Why? They have been waiting because they feel that if they get into Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), they can have an opportunity to utilise and develop their skills further. This is the situation going to respond to these people?

Therefore, I fully appreciate the hon. Minister for having brought forward this Bill. Sir, according to the statistics provided by him, only 2,58,000 people are getting this benefit. I request that it should be made a social obligation to be fulfilled by every industry. They must reserve a certain part of these opportunities for these poor people. There are plenty of people who are coming out of our ITIs with their diploma courses or coming out of evening colleges or coming out of engineering colleges. If they get these opportunities, they can develop their skills and enhance their efficiency which can further help in more and more production in the country. We have been exporting our manpower. People have been going abroad to earn money. But the inborn skills in our people ate not utilised here in our country. It is a pathetic situation. Pandit Nehru knew that this will be the fate of our country one day. That is why he had brought forward this law for giving these opportunities to people in Government of India establishments and also in aided and other institutions. Sir, I heard one song wherein it is said that cats and dogs are being adopted as pet animals in families, but we, the human beings, are thrown out of the families. That is the condition of the SCs, the STs and the OBCs.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Bill on behalf of my party, the DMK. This is one of the proudest moments. Whenever a move is made, from any quarter, to uplift the downtrodden, it becomes our bounden duty to stand by them and to extend our fullest support.

Sir, I recall that the first Constitution amendement was brought forward by Pandit Nehruji for providing reservations. The main reason behind that was my State of Tamil Nadu, our mentor, Periyar, and our founder leader, Anna. We all realise that, but for the toil of those leaders and the reform movements, we would not have been educated, we would not have risen to this level. And, forgetting all those past events the attitude of some people compels to realise something is still unpleasant. The social revolutionary movements in this country and the advent of scientific socialism uplifted the downtrodden people, the socially suppressed people, but yet, we come to know that there are still some Dronas who claim the thumbs of *Eklavyas* just because of the community they belong to. Skill is not recognized. However qualified a person may be, he is not recognised because of his community. As my colleague, Dr. Natchiappan pointed out once, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes people were treated as untouchables; they were not to be seen in the streets.

The meanest animals were allowed to stray along a street, whereas human beings were not permitted to walk. For thousands of years, we have struggled. We can recall the lives of our ancestors, the sad tale of theirs. They were deprived of education. If any person was interested in learning Vedas or something, it was advised that hot lead should be poured in his ears. It was not in those days only; Sir, it still continues. I am proud to say that I am from Tamil Nadu, that too, from the DMK Party of Periyar, Anna and our incumbent Chief Minister Dr. Kalaignar has enacted. so many progressive laws and has give enormous concessions to the backward people and the Scheduled Castes. I would like to inform the Members of this House that recently a law has been enacted in our State that people of all communities can become *archakas* in the temples. Those people who were not let into the temples can now enter into the sanctum sanctorum of the temples as *archakas.* This is the biggest revolution in this 21st century. So, this Bill has come at the right moment. I would like to thank the hon. Labour Minister for having introduced this amendment providing for reservation for OBCs in the Apprentices Act. This is more essential now because there is a huge backlog in the industries and offices because of lack of qualified and technically efficient students. This amendment paves the way for many of the backward community people who are efficient, to properly train them. It means, that backlog will not go to the general pool now. If the backlog is not fulfilled within a certain timeframe, it will automatically go to the general pool. Sir, like that, in this situation, this amendment is very essential. We have advanced; we have progressed, but still there are certain hurdles. The Government has to take into its hands all responsibilities to uplift the people. Those who were stumbling our way once socially are now trying to stumble our way legally. Only the Government by way of enacting laws, that too laws without any loopholes for anybody to enter in, have to implement it. That is the only way to uplift the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class people. Those efficient people are proving their talents abroad. To stop their exodus, Sir, we have to provide job opportunities for them. Now, employment is abundant whereas qualified students are lagging behind in number. This amendment will naturally satisfy the existing demand. Sir, on behalf

of the DMK Party I wholeheartedly appreciate the hon. Minister for having moved this amendment.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. Sir, my party colleague has already spoken on this Bill. I would like to support the Bill, and at the same time, share the anguish which my friend Dr. Natchiappan has just expressed. Sir, the question is, what would be the fate of this Bill, so far as its implementation and enforcement is concerned, whether it will meet the same fate like the Minimum Wages Act, the Working Hours Act and so on and so forth. This is a very important Bill. This is a very important requirement of the society, and please see to it that it is properly enforced. It is not only enforced on the Government companies but also enforced on the private companies. For this, some mechanism has to be found out. Thirdly, the practice that has developed very recently is, continuing with the apprenticeship and using them in the production process by paying that paltry stipend. Even in major public sector companies, it is now becoming a practice. I am not speaking of private sector because there the entire productive workforce is on contract and they are paid less than the minimum wage. That is a horrible kind of a situation that is prevailing there. So, in the matter of enforcement, please see to it that it is monitored and the apprentices are treated as apprentices only, and they are given training. But, they are. not used in the production process in lieu of stipend. You use them in the production process. Pay them their dues. Thirdly, I think, a serious linkage needs to be established in the process of apprenticeship and absorption in regular jobs. Otherwise, in the end if they do not get jobs, they will lose their skill and whatever they earn through apprenticeship. Again, I reiterate, the importance of stringent enforcement, both in public sector and private sector, and there must be a mechanism to force it on the private sector. Thank you.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : धन्यवाद होगा, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने वास्तव में एक क्रियाशील काम किया है और समाज के एक वर्ग को, जो मेहनतकश है, पिछड़ा वर्ग कहलाता है, उसके नौजवान के हाथों को रोजगार देने का काम किया है। यह एक प्रैक्टिकल काम है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, इस बिल का सपोर्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है, जैसाकि मेरे माननीय साथी ने भी अभी पूछा है कि हमने apprenticeship करा दी, इसके बाद उसकी नौकरी की क्या गारंटी होगी ? माननीय मंत्री जी को इसका कड़ाई से पालन कराना चाहिए। एक लड़के ने रोजगार के लिए apprenticeship की है, ट्रेनिंग प्राप्त की है, लेकिन कितना क्रियान्वयन हो पाता है? इसके लिए आई.टी.आई. के प्रिंसीपल, जिला सेवा जन कार्यालय के अधिकारी और जिला उधोग अधिकारी का निश्चित रूप से यह दायित्व बनना चाहिए कि हर जिला मुख्यालय पर एक कमेटी बनाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डी.सी. की अध्यक्षता में यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को apprenticeship दी गई है, उनको कितने प्रतिशत रोजगार मिले है।

मान्यवर, जिस समय अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में संशोधन करके आरक्षण दिया गया था, उस उस समय हमारे नेताओं के मन में जो अपेक्षाएं रही थी, शायद उनका क्रियान्वयन नही हो पा रहा है। अभी भी बहुत अनियमितताएं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों में महाराष्ट्र में एक कोन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में है। मध्य प्रदेश, यू.पी., हरियाणा में कोन है, लेकिन इनमें एक असमानता है। मैं माननीय मंत्री और सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध

करना चाहता हूं कि जब एक या एक से अधिक राज्य में कोई जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है तो उसे स्वतः ही राष्ट्रीय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग में मान लिया जाए । एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए अन्यथा इस आरक्षण और इस बिल का कोई फायदा अन्य पिछड़ा वर्ग को होने वाला नही है ।

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर का जाट, जो सबसे ज्यादा गरीब है, आज रोता है । चूंकि वह जाट है, भूमिहीन है, बॉर्डर पर बसता है, उसके बावजूद भी उसे कोई लाभ नही मिलता है । More than 30 per cent नौजवान के हाथ या पैर बम के विस्फोट में कट चुके है । वह रोता है,रोज दौड़ता है, लेकिन आरक्षण का लाभ नही पाता है । दिल्ली, राजस्थान का जाट आरक्षण का लाभ पाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जाट आरक्षण का लाभ नही पाता है । उसकी ननिहाल कहिए या ससुराल कहिए, साइंस कहती है कि मां और बाप का बेटे में बराबर हिस्सा है । जो बच्चा पिछड़े वर्ग की मां से पैदा हुआ है, पिछड़े वर्ग के बाप से पैदा हुआ है । जो बच्चा पिछड़े वर्ग की मां से पैदा हुआ है, पिछड़े वर्ग के बाप से पैदा हुआ है, आप उसे ओ.बी.सी. में रखेंगे या सामान्य श्रेणी में रखेंगे? यह एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन आई है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जिसकी माता पिछड़े वर्ग की है, जब वह बच्चा केंद्र पर नौकरी के लिए जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि तुम यू.पी. के जाट हो, अन्य पिछड़े वर्ग में आते ही नही हो । आरक्षण का उसे क्या फायदा होगा? लोगों की शादियां यह कहकर टूट रही हैं कि यहां का जाट तो अगड़ा है, वहां का जाट पिछड़ा है । मैं माननीय मंत्री और सरकार से आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां जिस जाति को उसके पैसे, उसकी खेती, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए एक या एक से अधिक राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए । एस.सी./एस.टी. में हमें कोई आपत्ति नही है कि कौन एस.सी. में है, कौन एस.टी. में है, परंतु केवल यह एक काम असमानता का है । एस.सी./एस.टी. में तो यह हो जाता है कि वह जाति पूरे देश में एस.सी./एस.टी. में आती है, परंतु ओ.बी.सी में यह एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है और ओ.बी.सी. में आपका यह वर्ग आता है । मैं किसी को निठल्ला नही कहना चाहता, परंतु मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि ओ.बी.सी. में जो जातियां हैं, वे सबसे मेहनतकश जातियां हैं । वे जातियां अंग्रेज राज में सबसे ज्यादा प्रताडित हुई है । उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है, आज भी सीमाओं पर सबसे ज्यादा शहादत करने का काम ओ.बी.सी. में आने वाले लोगों के बच्चे करते हैं, परंतु उनको उसका लाभ नही मिल पाता है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार से जो विसंगति छूट गई है, जो अनियमितता है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर दूर करने का प्रयास करें, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI ABDUL WAHAB PEEVEE (Kerala): Sir, I really appreciate the hon. Minister for bringing forward this amendment Bill before the House, even though it is late. A lot of reservation was there in Kerala. But, even after forty years or so, it was not effective, because there are a lot of loopholes in the system. In Kerala, because of Sachhar Committee Report, a lot of anomalies has been created. Now, through this Bill, the hon. Minister has brought a wonderful amendment. We appreciate and thank the hon. Minister for this. I once again thank him on my behalf and on behalf of my party. Thank you.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मेरी पार्टी ने सदन में आने माननीय सदस्य श्री राजनीति प्रसाद के माध्यम से इसका समर्थन किया है । आपने मुझे समय

दिया, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि श्री शरद जोशी जी ने दो-तीन बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए इसका विरोध किया है।

सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि समय की मांग के अनुसार उन्होंने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। इसके लिए सरकार और माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। वर्ण व्यवस्था को मेरिट के आधार पर नकारा नही जा सकता है। महोदय मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ ब्रिटिश हुकूमत कुछ चालबाजी करना चाहती थी। पाकिस्तान के निर्माण के मामले में उसने जैसी चालबाजी की, वैसी ही चालबाजी करना चाहती थी। डा. अम्बेडकर साहब ने इसको नही माना कि जैसे पाकिस्तान के निर्माण के नारे से धुआँ निकल रहा है, भारत के विखंडन को देखते हुए, उसी तरह इस देश में जो अछूत हैं, जिन्हें बाद में संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, उनके लिए एक अछूतिस्तान भी बने। जो सामाजिक में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, उनके लिए एक अछूतिस्तान भी बने। जो सामाजिक विभेद था, ब्रिटिश हुकूमत ने उसका लाभ उठाना चाहा, लेकिन अछूतिस्तान के नारे को बाबा साहब अम्बेडकर ने कबूल नही किया। पूना पैक्ट बना। पेरियार साहब हमारे पुरखे हैं, बाबा अम्बेडकर हमारे पुरखे हैं, महात्मा गाँधी हमारे नेता थे, वे राष्ट्रपिता थे। सब की कृपा हुई कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान हुआ। इस देश में शरद जोशी जैसे लोग कहते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता नही है, इससे जातीयता फैलती है। वे मेरिट की बात करते हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायपालिका में यह इश्यू जाएगा, फिर न्यायपालिका इसको रोकेगी। इन्होंने सही बात कही, क्योंकि न्यायपालिका का जो स्वभाव है, वह हठी स्वभाव हो रहा है। यहाँ जो संसद है, अगर आरक्षण नही होता, तो हो सकता है कि इस देश में मेरे जैसे लोग राजनीति में नही आते। लोकतंत्र नही होता, तो राजनीति नही होती और राजनीति हो रही है, इसलिए समता मूलक समाज की बात हो रही है। जब समता मूलक समाज की बात होगी, तो आरक्षण की बात होगी। आरक्षण की बात इसलिए होगी कि वर्ण व्यवस्था मूलक समाज है। देश में जो लोग वर्ण व्यवस्था मूलक समाज को नही समझते हैं या तो वे मूर्ख हैं या धूर्त्त हैं, दोनों में से कोई जरूर हैं। क्योंकि न्यायपालिका का चरित्र सामाजिक नही है। इस सदन का चरित्र सामाजिक है, क्योंकि समाज के हर वर्ग, हर समुदाय और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व यहाँ होता है। न्यायपालिका में अभिजात चरित्र है और न्यायिक स्वरूप है। अगर वहाँ अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग बैठे होते, तो क्रीमी लेयर नही होता। क्योंकि जोशी साहब, क्रीमी लेयर संवैधानिक व्यवस्था नही है। जब संसद को ताकत आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर जो निर्णय दिया, वह बदल जाएगा और बदलेगा। अभी सरकार ने तकनीकी संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान किया, न्यायपालिका जनशक्ति के सामने नही टिकेगी, क्योंकि sovereign पीपुल है। संविधान के अनुसार सर्वशक्तिमान जनता है और जनता की कोख से जब सरकार निकलेगी, तो सरकार परिवर्तन करेगी। इसलिए जो हठी बहुत दिलेर रहेगा और न्यायपालिका में जाएगा और न्यायपालिका रोकेगी, तो आने वाले दिनों में राजनीति होगी। यहाँ लोकतंत्र है और आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है ...(**समय की घंटी**)... इसलिए यह जन्मसिध्द अधिकार है। अतः मैं इनसे दो बाते कहना चाहूँगा कि यदि आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारी दो बातें मान लीजिए। पहली बात, कि जिसके पास मेघा है, जिसके पास सम्पत्ति है, जिसके पास भूमि है, उसी के पास नौकरी भी है। बँटवारा करो-'एक व्यक्ति एक रोज़गार, खेती, नौकरी या व्यापार'। संविधान में संशोधन करो कि जिनके पास भूमि रहेगी, उनको नौकरी नही होगी, उनका व्यापार नही रहेगा। जिनके पास व्यापार % होगा, उनको नौकरी नही होगी, उनके पास खेती नही होगी। आप संविधान में संशोधन कर दीजिए...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : शरद जोशी जी, **...(व्यवधान)...** नही नही **...(व्यवधान)...** आप बैठिए, बैठिए**...(व्यवधान)...**

श्री मंगनी लाल मंडल : दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि**...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : मंडल जी, अब आप समाप्त कीजिए**...(व्यवधान)...** ...(**समय की घंटी**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : आप पिछड़े वर्ग की जनगणना कराइए। **...(व्यवधान)...** महोदय, मैं कहता हूँ कि इस देश में सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। जिनकी जनसंख्या 5 प्रतिशत है, वे 60 प्रतिशत नौकरियों पर हावी हैं। इसलिए ऊँची जाति हो या पिछडी जाति हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जन जाति हो, सभी का हिस्सा बराबर हो। जनसंख्या के आधार पर आप सभी की जनगणना करा लीजिए । ...(**समय की घंटी**)... दो बातों के लिए यधपि शरद जोशी साहब तैयार हैं,**...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : आप क्यों बीच-बीच में उठ जाते हैं?**...(व्यवधान)...**

श्री मंगनी लाल मंडल : **...(व्यवधान)...** इसकी कोई व्यवस्था नही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और सरकार को तथा माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उडीसा) **:** मंडल जी, इस सदन में आरक्षण की व्यवस्था नही है। **...(व्यवधान)...** इस सदन में आरक्षण की व्यवस्था नही है। इसको भी कराइए और महिलाओं के लिए भी आरक्षण कराइए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) **:** माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत स्वागत करता हूँ कि वे इस विधेयक को लाए हैं तथा इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने एपरेंटिस में ओ0बी0सी0 को आरक्षण की चर्चा और उसको स्वीकृत कराने की बात की है।

समाज के पिछड़े वर्गो के लोग आगे आएँ, इस दृष्टि से उठाया गया कदम बहुत स्वागत-योग्य है। किन्तु माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मुझे तकनीकी शिक्षा मंत्री रहने का मौका मिला है । इस समय जिस परिमाण में आई0टी0आई0 में, पोलिटेकनिक में, इंजीनियरिंग कॉलेजज में महिलाएँ पढ़ाई के लिए आ रही हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनका भी आरक्षण वहाँ है। इन सब कॉलेजेज में, इन सब इंस्टीटयूशंस में अगर महिलाओं का भी आरक्षण है और उनकी रुचि बढ़ती चली जा रही है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ ओ0बी0सी0 को आरक्षण देने की बात उन्होंने कही, अगर इस बड़े परिमाण में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, इन सारी संस्थाओं में, संस्थानों में शिक्षा में आरक्षण है, तो क्या उनको नौकरी नही मिलनी चाहिए, क्या उनको दक्षता प्राप्त नही होनी चाहिए? अगर दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, तो उनको अप्रेंटिस की शिक्षा क्यों नही देनी चाहिए, अपरेंटिस क्यों नही बनाना चाहिए, उसमें आरक्षण क्यों नही होना चाहिए? यह मेरा सवाल है, जिस बात पर वे विचार करें।

मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने एक बात कही है। आजकल क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में जो विधेयक आए, ऐसा लगता है कि patch work किया जाता है । छोटी-सी समस्या आ गई, उस समस्या को उसमें लगा दिया गया और संशोधन आ गया। एक पूरे परिवेश में विचार करने की आवश्यकता क्यों नही है? जिस समय यह विधेयक लाया गया,

उस समय श्रीमन गुलजारी लाल नंदा मंत्री हुआ करते थे । उन्होंने इसके उद्देश्य को बताते हुए कहा है —The question of undergoing a Legislation for regulating the training of apprentices, in industry, has been under consideration of the Government for a long time. The expert committees, which went into the question, have recommended such a legislation. Although certain establishments in the public and the private sector have been carrying out programmes of training of skilled workers on a systematic basis, but Industry, in general, has not yet fully organized such programmes. In the context of the Five Year Plans and large scale industrial development of the country, there is an increased demand for skilled craftsmanship. The Government considers that it is fully necessary to utilise the facilities available for the training of apprentices and ensure their training in accordance with the programmes, standards, and syllabi drawn up by expert bodies उन्होंने तीन उद्देश्य बताए । पहला उद्देश्य बताया कि वे expertise हो जाएं । माननीय उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जो लड़के इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जो एम0बी0बी0एस0 करते है, जो पढ़ाई में अच्छे होते है, क्वालिटी वाले होते हैं, जिनका career बहुत अच्छा होता है, उनके तीन-तीन साल में campus interview होते है, उन्हें सीधे-साधे लोग उन्हें नौकरी पर लेने आ जाते हैं और बहुत अच्छे पैकेज देकर ले जाते है । महोदय, आज टैक्नीकल इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग करने वाले छात्रों के लिए नौकरी के द्वार खुल रहे है, किंतु जो mediocre होते हैं, जो पूरी शिक्षा प्राप्त नही कर पाते, केवल theoretical शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन को practical training की आवश्यकता है । इसलिए गुलजारी लाल नंदा जी ने कहा था कि दक्ष लोग तब बनेंगे जब उन को apprenticeship दी जाएगी । अगर आप का यह उद्देश्य है तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह विचार करने की आवश्यकता नही है कि जिस समय छात्र शिक्षा प्राप्त करें, उन इंस्टीटयूशंस का और इंडस्ट्री का आपस में linkage होना चाहिए ? कोई-न-कोई कानून क्यों नही बनना चाहिए, क्यों नही ऐसी बाधा उन इंस्टीटयूशंस पर लगाई जानी चाहिए कि वे interaction करें ताकि दक्ष लोग पहले से तैयार होने प्रारंभ हो जाएं । इसलिए मैंने कहा कि आप यह patch work कर रहे हैं । आप पूरी तरह विचार करें । लोगों को नौकरी मिले, इस के लिए apprentice की आवश्यकता है । आप इस में ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण ला रहे है, यह उचित है, किंतु जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस समय गुलजारी लाल नंदा ने बात कही, क्या वह पूरी नही हो रही है तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, इनका आपस में interaction होने की आवश्यकता है । उसी प्रकार यहां चर्चा हुई कि apprentice के समय stipend क्या दिया जाए ? मैं 5-6 हजार की बात नही करता,मंत्री महोदय, वह भी ठीक नही है । कम-से-कम जब आदमी नौकरी के लिए जाए, अगर वह आई0टी0आई0 पास है और किसी नौकरी में जाए, पॉलिटैकनिक पास है और किसी नौकरी पर जाए तो उस को ¾ of the pay apprentice के नाते मिलनी चाहिए । इस बात की बहुत आवश्यकता है । अगर आप ने यह कानून नही बनाया, यह बाधा नही डाली तो उचित नही होगा । महोदय, यह भी कहा गया है कि वह specified करेगी कि किस एरिया में apprentice करने की बात है । मेरा आप से निवेदन है कि जो Government Enterprises हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है, वे चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन के लिए compulsory बनाएं कि प्रत्येक को apprentice रखना आवश्यक है । इस बात की भी ताईद करिए । इसलिए एक full scaleमें, पूरा विचार कर के एक comprehensive Bill लाएं तो अच्छी बात होगी । अगर यह patch work करते रहेंगे तो इस का कोई फायदा नही होगा ।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। महोदय, अधिनियम की धारा 4 में कहा गया हैं कि The provisions of this Act shall not apply to any area or to any industry in any area unless the Central Government by notification in the Official Gazette specifies"जिस की चर्चा मैने की, उस को सीमित मत करिए, छोड़ दीजिए। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा महिलाएं है, handicapped हैं, इस प्रकार के कई handicapped persons हैं जिन के हाथ-पैर नही होने के बावजूद भी अगर उन्हें ट्रेनिंग मिल जाए तो वे बहुत अच्छा काम करने की स्थिति में है। क्या इस कानून को बनाते समय हमारे लिए उन बातों का प्रावधान करने की आवश्यकता नही है?

महोदय, ये तीन – चार बिंदु मैंने आप की मार्फत माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाने का प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि वह इन पर विचार करेंगे और एक comprehensive Bill इन सब बातों को लेकर बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. M.S. GILL (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for having given me the last minute opportunity. After listening to this debate and after reading this Amendment Bill, I felt I should say something. I thank you for allowing me to speak on this Bill. I will not take too much of time.

Sir, I support the Bill, and I congratulate the hon. Minister. Sir, I think, as far as I have seen, the whole House agrees with me. There are a couple of points I want to make. This is an Apprenticeship Bill. It has come all the way from Nehru's time, that is, 1961. I was just thinking that this is a Bill, which the Government should support financially, with facilities and with liberal stipends, in an unlimited way. This will help the Government because the problem of India is of providing employment. The problem of employment is getting training; worthwhile skilled training. Anybody who gets worthwhile skilled training does not need Government's or Minister's *sifarish.* - नौकरी मिल जाती है। India's economy is expanding. They need plenty of people who are able to do worthwhile technical jobs. Therefore, Sir, I would say to the hon. Minister, - in fact, to the Prime Minister and the Government because the Minister needs help from the Cabinet also - and, therefore, I put it further away that, in my opinion, this is a very important and vital part of this country's problem, with which the Prime Minister is struggling, and claiming to add so many jobs. So, for God's sake, if it has not happened before, give him all the money he needs. I think as a *Bharatnatyam* dancer, he will be very active and he will make sure that all the institutions come up. All the additional ones. ...*(Interruptions)*... Let me say. Please don't interfere. I am sure, if he is given the money, and if 10, 20 more institutions for training are needed, they will come up. Give them quality; give them staff, equipment and let as many boys and girls go as they can हिंदुस्तान को यह खर्चा महंगा नही पड़ेगा। In the scheme of things in your Budget, it is nothing. I don't want to attack anybody, but my hon. friend here was right to say that IITs and science institutes are all necessary. I do not oppose them. India needs them. वहां तो एकदम खर्चा कर देते है। This little thing is there, and, I say, give them all the money.

Secondly, he knows the technicalities of placing them, in putting them as apprentices and in getting them facilities. I believe it is legitimate for the Government, not only to do their own duty through the public sector or wherever they are, but

absolutely insist the private sector also. Whatever the Government thinks, they should give to any apprentices or any trainees coming in. If I may say so, even the SEZs should also do it one day.

Thirdly, I would like to add to what my friend said. I think it is a point missed. While this is for ensuring things for two, three categories including OBCs, I think, girls and women are important. They are a major part of our workforce. Today's girls, anywhere in India, have to learn what they can; they have to work. After marriage, they have also to support the family, sometimes, more than the husband. If they are pushed out, then, they have to support themselves and children. The man is gone. I would suggest to the hon. Minister that if it has not come in this Bill, please look at it and try to find a place for the girls of India in totality.

श्री ऑस्कर फर्नांडिस : उपसभापति महोदय, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस बिल को सपोर्ट किया और बहुत अच्छे सुझाव भी दिए। इस चर्चा में 15-16 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए, जिनमें रुद्रनारायण पाणि जी, आदरणीय संजीव रेड्डी जी, नन्द किशोर यादव जी, चन्द्रन पिल्लै जी, राजनीति प्रसाद जी, श्री जोशी जी, गांधी आजाद जी, मैडम दुर्गा जी, सुदर्शन नाच्चीयप्पन जी, शिवा जी, तपन सेन जी, हरेन्द्र मलिक जी, अब्दुल वहाब पीवी जी, मंगनी लाल मंडल जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी और श्री एम.एस. गिल जी हैं। इतने माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए है। यह बिल बहुत ही लिमिटेड परपज़ के लिए पेश किया गया है, फिर भी यह सारा संशोधन करना जरूरी है, एप्रेंटिसशिप एक्ट में यह सारा संशोधन करना जरूरी है। मैं हाऊस को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जितने सुझाव आज दिए गए हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको महिलाओं और फिजिकली हैंडीकेप्ड लोगों के बारे में सोचना है, उनको रिज़र्वेशन भी जरूर देना है। और अगर इस बिल को ज्यादा attractive बनाना है, तो इसके लिए stipend ज्यादा करने का सुझाव भी दिया गया है। लोगो के बाहर से आने के बाद उनकी कहीं ठहरने की व्यवस्था करनी जरूरी है, इसलिए stipend में increase करना है। उसके बारे में सारे stakeholders को हम बुलाएंगे और चर्चा करेंगे कि इस बिल में किन सुझावों को लाया जा सकता है। Important है training होने के बाद उनको industry में absorb करना। अभी तक कंडीशंस ये हैं कि सारे लोगों को इंडस्ट्री वाले जॉब्स होने के बावजूद भी absorb नही करते हैं, market से लोगों को लाते है। यह compulsory हैं Apprentices Act के मुताबिक, ट्रेनिंग देना compulsory है, इसलिए ट्रेनिंग देते है, फिर ट्रेनिंग के बाद ये लोगों को absorb नही करते, पब्लिक सैक्टर में भी नही करते, यह मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो पब्लिक सैक्टर में भी नही करते, यह मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो पब्लिक सैक्टर में भी कोआपरेट करना और उनको absorb करने के लिए उनका मन भी तैयार करना। इसलिए मैं हाऊस के सब मैम्बर्स को आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, इन सब सुझावों पर stakeholders को बैठकर चर्चा करेंगे और इस बिल में उन सुझावों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू को मैं आज याद करना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने उस समय इसके बारे में चर्चा की और आज हम लोग इस बिल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सिर्फ Apprentices Act के मुताबिक रिज़र्वेशन देने का मतलब नही है, backward लोगों को भी और SC, ST के लोगो को भी प्राइवेट सैक्टर ज़ॉब्स में रिज़र्वेशन देने की बात काफी मैम्बर्स ने कही है। इसके बारे में मैं अपने सुझाव या विचार नही कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया है, उसके बारे में मैं यहां पढ़ना चाहता हूं – "I invite corporate India to be a partner in making ours a more humane and just society. We need a new partnership for inclusive Growth based on what I would describe as

a Ten-Point Social Charterकी मीटिंग को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह भाषण दिया और एक मुद्दा और भी उठाया – Industry must be pro-active in offering employment to the less privileged, at all levels of the job ladder. The representation companies give to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and Women, in their workforce and staff must increase उसके अलावा उन्होंने कहा कि – Invest in people and in their skills. Offer scholarships to promising young people. Fill young people with hope in their future. High rates of growth mean nothing for those who are unable to find employment. We must invest in skill-building and education to make our youth employable. Here too, I appreciate the CII's initiative, CII in upgrading ITIs. This is a very good beginning, but there is more to be done यह प्रधानमंत्री जी की सोच है । प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि आज देश में जितनी लेबर फोर्स है, उसमें सिर्फ 5 प्रतिशत लोग skilled हैं । प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमें यह संख्या करीब 50 प्रतिशत तक पहुंचानी है ।चीन का एक प्रोवर्ब है कि कोई एक आदमी अगर आपके पास भूखा आता है तो आप उसको खाना मत दीजिए, खाने की जगह पर उसको मछली पकड़ने की शिक्षा दीजिए । Give them education how to fish. अगर skill में हमने उसको ट्रेनिंग दी तो बाद में वह आदमी धीरे-धीरे अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा । आज skilled workers की देश में जरूरत है । हमने देश में 500ITIs को world class level पर लाने का प्रोग्राम बनाया है । अभी last year 100 it is को upgrade किया गया । इस साल और 100ITIs को हम upgrade कर रहे है । इसके साथ ही अगले तीन सालों में हम 300 आई0टी0आईज़ को वर्ल्ड क्लास लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे है । इसके अलावा 1,300 आई.टी.आईज़ को हम पब्लिक, पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ढ़ाई करोड़ रुपए का interest free loan, उनको uplift करने के लिए दे रहे है, इसका फायदा भी हमारे लोगों को मिलेगा । आज इंडस्ट्री को trained hands की जरूरत है, technical hands की जरूरत है, इसमें यह अप्रेंटिस ऐक्ट उनकी मदद करेगा । हमारी इंडस्ट्रीज से यह अपील है कि इस ऐक्ट का वे पूरा फायदा उठाएं । गरीब लोगों को ज्यादा मदद चाहिए, इनमें SC/ST के लोग हैं , बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, महिलाएं हैं और सबसे ज्यादा जो handicapped लोग हैं, हमारी सब faculties ठीक हैं, फिर भी हम कहते है कि हमारे पास कुछ नही है, लेकिन ये जो physically handicapped लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं, इनको भी नौकरी देने का कम करना चाहिए, यह मेरी इंडस्ट्रीज के लोगों से अपील है ।

Stipend के बारे में हम जरूर ध्यान देंगे । जोशी जी ने एक बात कही थी, OBC के बारे में उनका रिज़र्वेशन है, मेरी उनसे अपील हैं कि वे हमें इस बिल को पास करने का मौका दें । यदि इस हाउस ने unanimously इस बिल को पास किया, तो देश में एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचेगा, यह मेरी उनसे अपील है । इतना कहकर, मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I put the motion to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Apprentices Act, 1961 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one amendment (No.2) by Shri Oscar Fernandes.

Clause 1-Short Title and Commencement SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, I move:-That at page 1, line 2, *for* the figure "2006", the figure "2007" be *substituted."*

The question was put and the motion was adopted.

Clause I, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment (No.l) in the Enacting Formula, by Shri Oscar Fernandes.

ENACTING FORMULA

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, I move:-

l. That *at page 1, line 1,* for the world "Fifty-seventh" the word "Fifty-eighth" be *substituted.*

The question was put and motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill. SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, I move-That the Bill, as amended, be passed. *The question was put and the motion was adopted. ...(Interruptions)...*

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, I ask for division. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Joshi, do you want *...(Interruptions)...*

AN HON. MEMBER: Sir, you have already said that the Bill is passed. *..(Interruptions)...*

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, I have voted against this idea three times and all the three times the Supreme Court has stood by me. I want it to happen the fourth time. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your opposition is on record.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I want it to be formalised, Sir. Is there any rule which permits you to say 'no' when one Member ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): Sir, he has already spoken on the Bill. And you have already said that the Bill is passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): It is already passed, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Joshi, the whole House is requesting you ... *(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF IN STATE THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, you have already said that the Bill is passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he stood up after you had said that the Bill was passed. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, the Chair has to give its ruling on my request. That is my right. ...*(Interruptions)*...

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, बिल पास होने के बाद बोल रहे है । बिल पास हो गया ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should have objected in the beginning. All the stages are over and the bill is passed now. Now, the Statement by the Minister.

SHRI SURESH PACHOURI: He is in the other House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We take up the Short Duration discussion on heavy floods. Ms. Pramila Bohidar. Not present. Shri Rudra Narayan Pany.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उडीसा) **:** महोदय, मैंने लिखकर दिया है कि श्री सुरेश भारद्वाज जी पहले बोलेंगे ।

श्री उपसभापति : आपका नाम है तो मैं बोल दिया । श्री सुरेश भारद्वाज जी । **SHORT DURATION DISCUSSION**

Heavy Floods in various parts of the country and relief measures undertaken by Government

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) **:**धन्यवाद उपसभापति जी । 14 अगस्त, 2007 को आदरणीय कलराज मिश्र जी ने सारे देश में बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न हुई है, उसके विषय में यह चर्चा प्रारंभ की है ।

(THE VICE-CHAIRMAN, SHRI UDAY PRATAP SINGH in the Chair)

हर वर्ष मानसून सत्र का प्रारंभ होता है और इस मानसून के सत्र में हर वर्ष हम बाढ़ अथवा सूखे के बारे में चर्चा करते है । कभी इस देश में सूखा पड़ जाता है और जिसके कारण सारे देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस होने की कगार पर पहुंच जाती है । पीने को पानी नही मिलता है, आदमी प्यासे मर जाते है, फसलें सूख जाती हैं, अनाज खराब हो जाता है और